



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में श्री रमाकांत भार्गव के निर्वाचित होने पर उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी।

उपचुनाव रिजल्ट के दूसरे दिन बाजार बंद

उपद्रव के डर से लिया निर्णय, टीआई बोले- गम्बर नहीं रहा, तो गम्बर के आदमी कहाँ से होंगे

श्यापुर (नप्र)। श्यापुर जिले के विजयपुर उपचुनाव के नतीजों में भाजपा के रामनिवास रावत को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7 हजार से ज्यादा वोट से हरा दिया। नतीजे आने के दूसरे दिन विजयपुर के सुनवाई रोड इलाके का बाजार बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि बाजार बंद कराने के लिए कोई आया हो या किसी ने कहा हो। असल में दुकानदारों ने उपद्रव की आशंका के डर से खुद ही बाजार बंद कर लिया। नतीजे वाले दिन भी शनिवार दोपहर करीब 2 बजे से बाजार बंद है रहा।

वैसे तो सुनवाई रोड इलाके में रोजाना दुकान सुबह 8:00 बजे खुल जाती हैं, लेकिन शनिवार दोपहर से लेकर रविवार सुबह 10 तक बजे तक दुकान नहीं खोली गई। बताया गया कि विजयपुर विधानसभा सीट पर जब-जब चुनाव होते हैं, तब



नतीजा चाहे किसी के भी पक्ष में आए, कुछ असामाजिक तत्व उत्पात मचाते पहुंच जाते हैं। पथराव, मारपीट और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं होती हैं। इसे देखते हुए दुकानदारों ने पहले से ही दुकान बंद करने का निर्णय लिया। इस बारे में दुकानदार विवेक जाटव का कहना है कि दूसरे लोग ने दुकान बंद की थी, इसलिए उन्होंने भी दुकान बंद की है।

विजयपुर थाना टीआई पप्पू सिंह यादव का कहना है कि परिणाम के बाद दुकान बंद हुई है, तो लोग सेलिब्रेशन करने चले गए होंगे। ऐसे में लोग सेलिब्रेशन के मूड में आ जाते हैं। कोई बात नहीं है क्योंकि, जब गम्बर ही नहीं रहा तो गम्बर के आदमी कहाँ रहेंगे।

संक्षिप्त समाचार

बिहार विधानसभा में बीजेपी की और बढ़ी ताकत

- 80 विधायकों के साथ बिहार विधानसभा में बन गई सबसे बड़ी पार्टी



पटना (एजेंसी)। बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है। चारों सीटों जीतकर एनडीए ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। इस जीत से जदयू, बीजेपी और हम के विधायकों की संख्या में इजाफा हुआ है, जबकि राजद और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। रामगढ़ और तारारी सीटों पर जीत के साथ ही बीजेपी अब 80 विधायकों के साथ सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं, बेलागंज सीट जीतकर जदयू के विधायकों की संख्या 45 हो गई है।

रूस ने यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाई अपनी 40 फीसदी जमीन

- कुरुर्क की 1376 स्क्वेयर किमी जमीन यूक्रेन ने कब्जाई थी

कीव (एजेंसी)। यूक्रेन ने अगस्त में रूस के कुरुर्क इलाके में अचानक हमले किए थे। इस दौरान यूक्रेन ने कुरुर्क के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। हालांकि अब रूस



ने यूक्रेन के कब्जे में से 40 फीसदी जमीन को वापस छीन लिया है। इसकी जानकारी यूक्रेन के जनरल स्टाफ के एक अधिकारी ने दी। अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन ने कुरुर्क प्रांत में 1376 स्क्वेयर किमी जमीन कब्जा कर लिया था।

अब देश में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी बीएसपी

- खराब नतीजे के बाद मारावती का बड़ा ऐलान, ईवीएम पर फोड़ा टीकरा



लखनऊ (एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मारावती ने उपचुनाव के नतीजों के बाद बड़ा फैसला किया है। उन्होंने देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि बैलेट से धांधली तो होती ही थी अब ईवीएम से भी धांधली होने लगी।

इसलिये बसपा ने यह निर्णय किया है कि वह देश के किसी भी राज्य में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। यूपी की पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा, यूपी में 9 सीटों पर हुए चुनाव और फिर उसके नतीजे के बाद लोगों में ईवीएम को लेकर आम चर्चा है। पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे। अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है।

भोपाल आलमी तब्लीगी इज्तिमा में 4 फूड जोन

टेंट, टॉयलेट, सड़कों का काम पूरा ; 28 से आएंगी जमातें



भोपाल (नप्र)। भोपाल में 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक आलमी तब्लीगी इज्तिमा होना है। तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। टेंट, टॉयलेट, फूड जोन, सड़कों का काम तो पूरा कम्प्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक वर्क 10 प्रतिशत बचा है। यह भी अगले दो दिन में पूरा कर लिया जाएगा।

इज्तिमा कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उमर हफ्ज ने बताया-28 नवंबर से जमातें भी आना शुरू हो जाएंगी। इस बार इज्तिमा की थीम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रखी गई है।

300 से ज्यादा जमातें आएंगी- इस बार 300 से ज्यादा जमाते इस इज्तिमे में आएंगी, जो 28 नवंबर तक भोपाल पहुंचेंगी। इस बार 600 एकड़ एरिया में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 300 एकड़ में पार्किंग, 100 एकड़ में टेंट लगाया जा रहा

है। 200 एकड़ एरिया में दूसरी व्यवस्थाएं जैसे- फूड जोन, वुजू खाने, वॉशरूम बनाए गए हैं। 4 फूड जोन बनाए गए हैं। इंटरनल फूड की 28 शॉप, 21 नाश्तें और पानी के लिए भी कई शॉप्स हैं, जो करीब 80 के आसपास हैं। 300 शॉप्स होटल की हैं।

इस बार 12 लाख लोगों के आने की उम्मीद- इस बार के इज्तिमा में मेट्रो निर्माण का काम रुकावट नहीं बने, इसलिए भोपाल टॉकीज से करीद तक के एरिया में बैरिकेडिंग कम की जाएगी। इज्तिमा के पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक 8 लाख लोग जमा होते हैं। आखिरी दिन दुआ में शामिल होने के लिए 4 लाख से अधिक लोग और पहुंचते हैं। इस बार 12 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है।

यूपी के संभल में भारी हिंसा, तीन लोगों की मौत

कमिश्नर ने कहा-छत्तों से फायरिंग हुई, परिजन बोले-पुलिस की गोली से मौत



लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। हालात कई घंटे से बेकाबू है। कई घंटों तक गलियों में जगह-जगह पथराव होता रहा। उस भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पथराव में एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। डिप्टी कलेक्टर भी चोटिल हुए हैं। एक पुलिसवाले को भी गोली लगी है। इधर, अखिलेश यादव ने लखनऊ में दावा किया कि संभल में बीजेपी ने बवाल कराया है। ताकि चुनाव में की गई धांधली की चर्चा न हो। दरअसल, सुबह 6.30 बजे डीएम-एसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। टीम देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। कुछ ही देर में करीब दो हजार से ज्यादा लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई।

मणिपुर हिंसा

सुरक्षाबलों की 288 कंपनियां तैनात, इंफाल घाटी में सर्चिंग

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर लगी रोक को दो दिन के लिए और बढ़ाया गया। इंफाल पश्चिम, इंफाल



सर्विस बैन की गई थी। मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। गुह विभाग ने नोटिस जारी किया है। इससे पहले 19 नवंबर को सरकार ने ब्रॉडबैंड सर्विस से बैन हटाया था। जिससे स्कूल-कॉलेजों, अस्पतालों, सरकारी ऑफिसों के काम नहीं रुके। वहीं, 16 नवंबर को विधायकों

के घरों में तोड़फोड़-आगजनी के मामले में 2 और लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक और भी लोगों की तलाश की जा रही है। इसके लिए इंफाल घाटी में सर्चिंग जारी है। 11 नवंबर को जिरिबाम में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 10 कुकी-जो अग्रवाधियों को मार गिराया था।

- सात जिलों में लगा इंटरनेट बैन दोदिन और बढ़ाया, विधायकों के घर पर हमले मामले में अब तक 34 गिरफ्तार

पूर्व, काकचिंग, बिष्णुपुर, थांबल, चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में 16 नवंबर को पहले दो दिन के लिए इंटरनेट

बुरे फंसे नेतन्याहू, भविष्य पर खड़े हुए सवाल

- विदेशमें गिरफ्तारी वारंट, इजरायलमें चल रहा भ्रष्टाचार का मुकदमा

तेल अविव (एजेंसी)। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तर पर कानूनी मामले चल रहे हैं। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गुरुवार को नेतन्याहू के खिलाफ गाजा में युद्ध अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू को इजरायल में भी भ्रष्टाचार के एक मुकदमे में गवाही देनी है। दोनों ही मामले उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल में लंबे समय से भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है।

नई दिल्ली/ भोपाल/ जयपुर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ अब हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल के कुल्लू जिले के रोहलांग पास और अटल टनल के पास रविवार को बर्फबारी हुई। वहीं, जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, गुलमर्ग, बांदीपोरा और लद्दाख के लेह में भी रविवार को बर्फबारी हुई। तीनों राज्यों में सोमवार को भी बर्फ गिरने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने देश के 8 राज्यों में घना कोहरा छाने का भी अनुमान जताया है। इन्में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल

तीन राज्यों में बर्फबारी 9 में छाया घना कोहरा

- एमपी-राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 15 शहरों में तापमान लगातार दूसरे दिन 10 डिग्री से नीचे



प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तापमान लगातार दूसरे दिन 10 डिग्री से नीचे रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के बाद वहां से आई बर्फाली हवा के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान में ठंड लगातार बढ़ रही है। एमपी और राजस्थान 7-7 स्थानों और

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तापमान लगातार दूसरे दिन 10 डिग्री से नीचे रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के बाद वहां से आई बर्फाली हवा के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान में ठंड पड़ रही है।

इंदौर के एडिशनल डीसीपी को डिजिटल अरेस्ट का कॉल

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में पदस्थ एडिशनल डीसीपी को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। वे रविवार दोपहर करीब 2 बजे अपने दफ्तर में बैठे थे। तभी एक कॉल आया। बताया कि आपके क्रेडिट कार्ड से गलत तरीके से एक लाख 11 हजार रुपए 930 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसकी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद स्टेटमेंट लेने के लिए अफसर को वीडियो कॉल किया गया। जिसमें वर्दी में देख उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।

कहा- 2 घंटे में आपको थाने आना पड़ेगा- एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि मुझे एक ऑटोमैटेड कॉल आया। जिसमें बताया गया कि आपके क्रेडिट कार्ड का मिस्यूज हुआ है। 2 घंटे के अंदर आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। मुझे लगा कि यह डिजिटल अरेस्ट का मामला है। मैं उनसे बात करता रहा। पूछता रहा कि मुझे क्या करना होगा। उन्होंने बताया कि हम आपको इतनी मदद कर सकते हैं कि आपको थाने में कनेक्ट करा देंगे। इसके बाद उन्होंने मुझे थाने में कनेक्ट करा दिया। वहां एक ठग ने पुलिस कर्मी बनकर बात की।

कहा-2 घंटे में बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, वर्दी में देख भाग खड़ी हुई नकली पुलिस



बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है। आपके खिलाफ अंधेरी वेस्ट में एफआईआर हुई है। आप मुंबई कब आए थे, मैंने जवाब दिया कि मैं तो 10 साल से इंदौर आया ही नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा कि 2 घंटे में आपको थाने आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं इंदौर रहता हूं। 2 घंटे में आना संभव नहीं है। उनका जवाब था कि हम आपके हमारे अफसर से

बात कराते हैं। वह अंदर गया, वहां जय हिंद कहा और बताया कि एक डिजिटल का मामला है। स्टेटमेंट ले सकते हैं क्या, परमिशन है। इसके बाद मुझे वर्दी में देखकर उन्होंने कहा कि आपके साथ कौन है, तो मैंने आपकी थाने आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं इंदौर रहता हूं। इसके बाद उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने

बताया मैं उस वक्त मीडिया को रूटीन ब्रीफ करने जा रहा था। तभी यह कॉल आया। मैं समझ गया था कि डिजिटल अरेस्ट करने वाला फ्रांड़ का है। सोचा इसे रिकॉर्ड कर लोगों को अवेयर किया जा सकता है।

पीएम ने फिर किया डिजिटल अरेस्ट का जिक्र

नवंबर के आखिरी रविवार को मन की बात का 116वां एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। नवंबर के आखिरी रविवार को मन की बात का 116वां एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात रेडियो शो के 116वें एपिसोड में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती, एनसीसी दिवस, गयाना यात्रा, लाइब्रेरी जैसे मुद्दे पर बात की। पिछली बार की तरह पीएम मोदी ने कहा- हमें बार-बार लोगों को समझाना होगा कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक खुला झूठ और लोगों को फंसाने की साजिश है।

प्रतिबंधित बीआरटीएस लेन पर भाजपाइयों की रैली

इंदौर में संविधान गौरव यात्रा को लेकर अफसर बोले- हमें अनुमति मार्ग का पता नहीं



इंदौर (एजेंसी)। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इंदौर बीआरटीएस को हटाने की घोषणा करने के चौथे दिन ही भाजपाइयों ने प्रतिबंधित रास्ते पर वाहन रैली निकाली। इसके चलते बसों को बीआरटीएस छोड़कर अन्य वाहनों के साथ चलना पड़ा। देवास नाका से राजीव गांधी चौराहे तक 11.5 किमी लंबे बीआरटीएस पर केवल आई बस और एम्बुलेंस ही चल सकती है। दरअसल रविवार को इंदौर में भाजपा ने संविधान गौरव यात्रा निकाली। यह यात्रा विजय नगर से महु तक जाना प्रस्तावित थी। विजय नगर से राजीव गांधी चौराहे तक यह यात्रा बीआरटीएस बस लेन पर निकाली गई। इससे आई बस को सामान्य वाहनों

की लेन में चलना पड़ा। बस स्टेशनों पर इंतजार कर रहे यात्रियों को भी इससे असुविधा हुई। भारतीय जनता पार्टी अजा मोर्चा की यात्रा बलजीत सिंह चौहान की अगुवाई में विजय नगर से यह यात्रा निकाली गई। वाहनों पर तिरंगे झंडे लगे थे। पूरी बस लेन में कारों का ही काफिला नजर आने लगा। यह यात्रा महु के वेटरनरी कॉलेज पर समाप्त हुई। आयोजकों का कहना है कि, हमने यात्रा के लिए प्रशासन से अनुमति ली थी, हालांकि बस लेन से वाहन ले जाने को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी ने बताया कि, अनुमति किस मार्ग की थी। हम पता करवा रहे हैं।

बुंदेलखंडी लोकगीत ‘फंस गई जल मछली’ पर थिरके इंदौर महापौर

कजिन की शादी के महिला संगीत का वीडियो आया सामने

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव का डांस करते हुए एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वे बुंदेलखंड के लोकगीत ‘फंस गई जल मछली’ पर जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ मंच पर परिवार के कई अन्य पुरुष सदस्य भी ताल से ताल मिला रहे हैं।

बताया जा रहा है कि 22 नवंबर को बायपास स्थित रास बुंदवन गार्डन में महापौर की कजिन की शादी के महिला संगीत का आयोजन रखा गया था। यहां महापौर अपने परिवार के साथ मौजूद थे। डांस करते समय उनके परिजन ने ही यह वीडियो शूट किया। यह वीडियो रविवार को सामने आया है।

इंदौर में एनआरआई समित 16-17 दिसंबर को 25 से ज्यादा देशों के एनआरआई आएंगे; इंदौर के विकास पर होगा मंथन

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में 16 और 17 दिसंबर को एनआरआई समिट का आयोजन होगा। यह प्रवासी इंदौरियों के सम्मेलन का तीसरा वर्ष है। मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में 25 से अधिक देशों के एनआरआई शामिल होंगे। समिट का उद्देश्य इंदौर और दुनिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा, इंदौरी एनआरआई और स्थानीय लोगों के बीच संवाद बढ़ाना, इंदौर की संस्कृति और विकास के बारे में जानकारी देना और इंदौर के विकास कार्यों पर चर्चा करना है। पिछले साल भी इंदौर में आयोजित एनआरआई समिट में दुबई, अबु धाबी, शिकागो, सेन फ्रांसिस्को, जापान सहि दुनिया के 28 देशों के एनआरआई इंदौर पहुंचे थे।

शॉपिंग मॉल की कैशियर के साथ रेप शादी का झांसा देकर दोस्त चार साल से कर रहा था शोषण



इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में एक शॉपिंग मॉल की कैशियर के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी और युवती कभी दोस्त हुआ करते थे। शादी का झांसा देकर वह चार साल से उसका शोषण कर रहा था। द्वारकापुरी पुलिस के मुताबिक, युवती की शिकायत पर पुलिस ने शुभम राठौर के खिलाफ रेप और धमकाने की एफआईआर की है। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। युवती ने बताया कि चार साल पहले से वह शुभम को जानती है। हमारी फ्रेंडशिप हुई, तो शुभम के साथ घूमना-फिरना होने लगा। आरोपी ने एक दिन उसे प्रपोज किया। कहा कि प्यार करता है और शादी करना चाहता है। हमारे बीच रिलेशन हो गए। जब भी उससे शादी करने की बात करती, तो वह टाल देता। आखिरी बार वह 25 जुलाई को गोपुर इलाके की एक होटल में लेकर गया। यहां भी रिलेशन बनाए। युवती का कहना है कि आरोपी ने अब दूरी बना ली है। मोबाइल नंबर और आईडी ब्लॉक कर दी। शनिवार, 23 नवंबर को उसके घर पहुंची, तो वह अपशब्द कहने लगा। इसके बाद वहां से भाग दिया।

कूलर गोदाम में आग लगी, कर्मचारी जिंदा जला

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में देर रात कूलर गोदाम में आग लग गई। हदसे में एक कर्मचारी जिंदा जल गया। आग की चपेट में गोदाम के बाजू में बनी दो और दुकानें आ गई। करीब दो घंटे की मशक़त के बाद फायर ब्रिगेड ने लपटों पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक, हदसा लसूडिया मोरी के पांचाल कंपाउंड में रात दो बजे हुआ। आग श्याम कूलर के गोदाम में लगी, जो कृष्णा मोटर वाईडिंग और एक अन्य लोडिंग गाड़ियों की वर्कशॉप तक पहुंच गई। कूलर गोदाम के भीतर राजू नाम का कर्मचारी सो रहा था। उसने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन धुएं के चलते कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस को उसका जला शव मिला है। राजू पिता गया प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुरा का रहने वाला था। दो साल पहले काम करने इंदौर आया था।

कर्मचारी ने फोन पर कहा था— शॉर्ट सर्किट हो गया

पुलिस ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। प्लास्टिक के कूलर, घास के पैड और दूसरे

इंदौर में मालिक को फोन किया था-शॉर्ट सर्किट हो गया, पड़ोस में बनी दो दुकानें भी जलीं



ज्वलनशील मटेरियल की वजह से यह तेजी से फैल गई। टीआई तारेश सोनी ने कहा, राजू ने अपने मालिक

को कॉल कर शॉर्ट सर्किट की जानकारी दी थी। मालिक ने कुछ देर में आने की बात कही। राजू ने अपना मोबाइल

भाजपाइयों ने देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म

सांसद पाटीदार बोली- गोधरा कांड में हुई घटना की सच्चाई सामने आई

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में रविवार को भाजपाई द साबरमती एक्सप्रेस मूवी देखने एक साथ पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार और भाजपा के जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा भी साथ थे। सभी एक साथ महु स्थित विक्रम मॉल के थिएटर में पहुंचे। मूवी देखने के बाद सांसद पाटीदार ने कहा कि, गोधरा में हुई घटना पर आधारित इस फिल्म ने तब की सच्चाई जनता के सामने लाने का काम किया है। पुरानी घटना की सच्चाई को दबाकर कारसेवकों के बलिदान को गलत रूप में पेश कर देश-दुनिया को भ्रमित किया था। जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने कहा कि, 2002 में गुजरात के गोधरा में हुई घटना एक सोची समझी साजिश थी। इसे दुर्घटना का नाम देकर देश की जनता से सच्चाई छुपाई गई। उन्होंने फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने का निर्णय के लिए मुख्यमंत्री



डॉ. मोहन यादव का आभार जताया। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे भी एयरपोर्ट रोड स्थित सिने स्क्रेयर सिनेमा में द साबरमती मूवी देखने पहुंचे। भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ द्वारा फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। नगर अध्यक्ष मनोज ठाकुर, माया पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं युवा बात कार्यक्रम भी सुना। यहां उन्होंने

नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्षों का स्वागत एवं सम्मान किया। भाजपाइयों ने मूवी का मोबाइल की टॉर्च जलाकर समर्थन किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष घनश्याम नारोलिया, कोषाध्यक्ष हेमचंद मित्तल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मनोज ठाकुर, माया पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं युवा उपस्थित थे।

इंदौर में सीढ़ी से गिरी 3 साल की बच्ची,मौत

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के कनाड़िया में खेत पर काम करने वाले मजदूर की तीन साल की बेटी की सीढ़ियों के पास पत्थर पर गिरने से मौत हो गई। उसके सिर और सीने में चोट आई थी। खून का थक्का जम गया था। रात में बच्ची ने एमवाय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कनाड़िया पुलिस ने बताया कि राधिका (3) पुत्री जितेन्द्र ठाकरिया,

निवासी ग्राम कनाड़िया की मौत हुई है। 15 नवंबर को वह अपनी बहन और भाई के साथ खेल रही थी। इस दौरान वह सीढ़ियों से फिसलकर पत्थर पर जा गिरी। पहले उसे शंकुतला अस्पताल ले जाया गया। यहां पर उपचार मंहगा होने के चलते उसे शनिवार रात एमवाय अस्पताल लेकर लेकर आए थे। रात में बच्ची ने यहां दम तोड़ दिया।

गुजरात से इंदौर आई 6 साल की बच्ची लापता



मानसिक रूप से कमजोर बच्ची बोलने में भी असमर्थ, दादा-दादी से मिलने आई थी

इंदौर (एजेंसी)। माता-पिता के साथ गुजरात से इंदौर के राजेन्द्र नगर आई 6 साल की बच्ची लापता हो गई। परिवार शनिवार रात थाने पहुंचा। यहां जानकारी के बाद पुलिस और परिवार बच्ची की तलाश में जुट गया है। बच्ची बोल नहीं पाती। बताया जा रहा है कि बच्ची मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर है और बोलने में असमर्थ है।

जानकारी के अनुसार शनिवार शाम राजेन्द्र नगर थाने पर जीवन मोणा और उनके परिवार के लोग पहुंचे थे। उन्होंने यहां 6 साल की बेटी लक्षिका की गुमशुदगी दर्ज कराई है। जीवन ने बताया कि वह गुजरात के सुरेन्द्र नगर में फार्मा कंपनी में काम करते हैं। पत्नी और दो बच्चों को लेकर शिव सागर कॉलोनी में रहने वाले माता-पिता से मिलने इंदौर आए थे। दोपहर में पत्नी शालिनी मोणा नजदीक ही स्थित एक ब्यूटी पार्लर गई थी। पत्नी कॉल करने पर बेटी को बाल कटवाने के लिए भेजने का कहकर गई थी।

दोपहर करीब 1 बजकर 35 मिनट पर पत्नी शालिनी का कॉल आया कि बेटी को भेज दो। उस समय जीवन खाना खा रहा था। उसने चचेरे भाई ऋषि से लक्षिका को उसकी मम्मी के पास छोड़ कर आने के लिए दूढ़ा, लेकिन वो नहीं मिली। आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछा, लेकिन तब भी उसकी जानकारी नहीं लगी। काफी देर तक खोजने के बाद परिवार ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है।

संपादकीय

महाराष्ट्र- कौन बनेगा मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की महाविजय के बाद यह महासवाल भी सियासी हल्कों में तेजी से चल रहा है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देवेन्द्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या फिर अजित पवार है। चुनाव में महायुति के तीनों घटकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जो नतीजे आए हैं, उसकी तो महायुति को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस प्रचंड विजय ने राज्य कमना किसके हाथ की मुग्ध और संजीदा बना दिया है। अगर महायुति के मुख्य घटक भाजपा की बात की जाए तो चुनाव 132 सीटें जीतकर वह तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। यानी 14 विधायक और जुटा ले तो उसकी अपनी सरकार बन सकती है। लेकिन भाजपा ऐसा शायद ही करेगी, क्योंकि इससे गठबंधन धर्म का अपमान होगा तथा सहयोगी दलों में भाजपा की नीयत को लेकर गलत संदेश जाएगा। जिसका दुष्परिणाम दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। शिवसेना शिंदे गुट ने भी 57 सीटें जीतकर उद्धव सेना को बौना बना दिया है। दो साल पहले एक रणनीति के तहत मात्र 40 विधायकों वाली शिवसेना (शिंदे) के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर और अपनी पार्टी के सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार देवेन्द्र फडणवीस को उपमुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था। फडणवीस ने भी पार्टी के आदेश की शिरोधार्य करते हुए छिट्टी सीएम बनकर काम किया। उनकी और शिंदे की ट्यूनिंग भी अच्छी रही है। लेकिन चुनाव में बंपर सीटें जीतने के बाद भाजपा कार्यकर्ता यह मान जाँरे से उठा रहे हैं कि पार्टी पिछली बार की तरह कोई 'त्याग' न करे और देवेन्द्र को ही सीएम बनाए। वैसे भी भाजपा में देवेन्द्र फडणवीस ही सीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। उधर शिवसेना शिंदे के विधायक एकनाथ शिंदे को ही फिर से सीएम बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। क्योंकि शिंदे के नेतृत्व में चली सरकार के काम पर ही मतदाताओं ने सकारात्मक वोट दिया है। वैसे सीएम पद के तीसरे दावेदार अजित पवार भी हैं, लेकिन उनकी दावेदारी बहुत मजबूत नहीं है। वो फिर से उपमुख्यमंत्री बनकर संतुष्ट रहेंगे। बड़ा सवाल शिंदे के सामने है कि अगर वो सीएम नहीं रहे तो क्या बनेंगे और मुख्यमंत्री पद नहीं दिया तो क्या वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे? शिंदे की मुश्किल है कि यदि उन्होंने महायुति से बाहर निकलना का फैसला किया तो खुद उनकी पार्टी में भी बगावत हो सकती है। शिंदे के विधायक कतई नहीं चाहेंगे कि केवल सीएम पद की मांग के चलते पांच साल विपक्ष में बैठना पड़े। वैसे भाजपा सहित तीनों घटक पार्टियां सार्वजनिक रूप से यही कह रही है कि सीएम पद का मसला तीनों पार्टियों के शीर्ष नेता मिल बैठकर सुलझ लेंगे। यह भी संभव है कि सीएम पद की दावेदारी छोड़ने की ऐवज में शिवसेना (शिंदे) को मुंबई महानगर पालिका के मेयर पद का या केन्द्र में कैबिनेट मंत्री बनाने की पेशकश की जा सकती है। लेकिन शिंदे इस पर शायद ही राजी हों। अगर वो विपक्ष के साथ जाना भी चाहें तो मआवि के विधायकों की संख्या इतनी कम है कि उनके समर्थन से वो कोई सरकार बना सके। वैसे भी इस चुनाव में जनता का आदेश महायुति के पक्ष में है। जो महायुति तोड़ना, उसे गंभीर खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह संभव के अगले सा बिहार विधानसभा चुनाव तक शिंदे को ही सीएम बनाए रखें और उसके बाद उन्हें स्वेच्छ से पद छोड़ने को कहा जाए। शिंदे क्या करेंगे, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। यह भी संभव है कि भाजपा नेतृत्व इस मामले में भी कोई चौकाना वाला फैसला करे।

प्रसंग

चित्रा माली

लेखक गाँधी एवं शांति अध्‍ययन विभाग महत्वा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में सहायक प्रोफ़ेसर हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस महिलाओं के प्रति हिंसा,शोषण और उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के उन्मूलन हेतु संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंध 25 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है । इस दिन का अपना एक इतिहास है। 125 नवंबर 1960 में तीन बहनों (पेंट्रिया,मारिया,एंटोनिया) की सामूहिक हत्या डोमिनिक तानाशाह शासक राफेल ट्रिज़ल्लों ने करवाई थी। इन बहनों की हत्या महज इसलिए करवाई गई थी कि वे अपने अधिकारों के लिए तानाशाह के खिलाफ लड़ रही थी। 1981 में महिला अधिकारों के समर्थकों ने उन तीन बहनों की स्मृति में महिला हिंसा के खिलाफ इस दिन को मनाने की शुरुआत की। 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 'महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन की घोषणा' करते हुए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को परिभाषित भी किया था इसके अनुसार लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक,यौन संबंध स्थापित होते है या स्थापित होने की संभावना है तथा महिलाओं को मानसिक क्षति या पीड़ा पहुंचना भी हिंसा है। इसके अतिरिक्त किसी भी महिला को डराना,धमकी देना या उन्हें उनकी स्वातंत्रता से वंचित करना भी हिंसा की श्रेणी में आता है यह सार्वजनिक और निजी दोनों जीवन में शामिल हैं । महिला हिंसा के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए 1999 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महिला हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम के

सुबह सवरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए

उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. ईफ़्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बाँबे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी

संपादक (म.प्र.) - गिरिश उपाध्याय

वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल

स्थानीय संपादक - हेमंत पाल

प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,

Mobile No.: 09893032101

Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

यह कहना विचित्र सा लगेगा कि दुनिया एकता की तलाश विभेद में करती है। विशेषतः एशियाई देश जिसमें भारत भी शामिल है, इस अनिश्चितता की समस्या से मुक्त नहीं है। बीसवीं सदी के मध्य में दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था, संयुक्त राष्ट्र संघ : दुनिया दो सामरिक धड़ों में विभाजित थी एक नाटो (नार्थ एटलांटिक ट्रीटी) दूसरा नाटो मुख्तः अमरीकी शक्ति के साथ चलने वाले देशों का संगठन था। दूसरा रूस, चीन व कम्युनिस्ट देशों की ताकत के साथ एक सम्मोज्द का संगठन है। नाटो, रूस, चीन के खतरों के विरुद्ध अपने संगठन के देशों को सुरक्षा मुहैया कराता था। दूसरा अमेरिकी याने नाटो के हमलों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया संगठन था। उस समय दुनिया इन दो ही शक्ति के धड़ों में विभाजित थी। परन्तु कालान्तर में कईशक्ति के केंद्र उभरे हैं और नाटो और दूसरे की भूमिका या तो सिकुड़ी हैयाबिखरी है। 1950 में आजादी के बाद भारत दोनों धड़ों से अलग था। और उसने भारत, अरब, युगोस्लाविया आदि देशों के साथ गुटनिरपेक्ष देशों का एक संगठन तैयार करने में सहभागिता की। 1950 और उसके बाद नेहरू, नासिर, टिटो की चर्चा दुनिया में युद्ध व हथियार की शक्ति से हटकर एक निर्गुट संगठन बनाने के रूप में हुई थी। इस गुटनिरपेक्ष विदेश नीति ने भारत और दुनिया को दो शक्तिशाली धड़ों के प्रभाव से बचाकर एक मंच विकसित करने की आशा जगाई थी। हालांकि इस गुटनिरपेक्ष संगठन के ये तीन देश सामरिक, आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं थे और अर्थ व शस्त्र से समर्थ दुनिया का कोई मजबूत विकल्प या उस ताकतवर दुनिया से पीड़ित देशों के लिए कोई सुरक्षा देने की स्थिति में व्यावहारिक रूप से नहीं थे। ये केवल एक नैतिक समर्थन कर सकते थे। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति यद्यपि केवल नेहरू सरकार की देन नहीं थी बल्कि यह आजादी के आन्दोलन और महात्मा गाँधी की काँग्रेस की देन थी। डॉ. लोहिया के जर्मनी से पढ़कर लौटने तथा काँग्रेस में सक्रिय होने के बाद उन्हें काँग्रेस पार्टी के विदेश विभाग का सचिव बनाया गया था। गुटनिरपेक्ष नीति के दस्तावेज डॉ. लोहिया ने ही तैयार किया था। जिस पर काँग्रेस व तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल ने मोहर लगाई थी। इक्कीसवीं सदी के आते-आते सामरिक तन्त्रके में शक्तियों के केंद्र बदल गए हैं अब दुनिया के फ़रवीय नहीं रही बल्कि एक अर्थ में बहु फ़रवीय बन गई है। चीन भले ही रूस का वैचारिक भाई रहा परन्तु उसने कभी भी अपने मन से रूसी श्रेष्ठता या वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया। 1960 के बाद तो, याने चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के त्प्याह वर्ष बाद चीन ने अपनी वैश्विक व विदेश नीति की भूमिका को रूस से स्वतंत्र रूप से अदा करना शुरू कर दिया था। 1960-70 के बाद चीन-रूस के भी समानांतर खड़े होने लगा। अपने प्रभाव का फैलाव आसपास के देशों में करने लगा था। 1959 में उसने

हिंसा के बढ़ते आंकड़ों के बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस

तहत 2008 से 2030 तक एक UNITE Campaign चलाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के फलस्वरूप ही 155 देशों में 'घरेलू हिंसा' पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाए गए हैं तथा 140 देशों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बनाए हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला संघ की स्थापना भी संयुक्त राष्ट्र सुधार कार्यक्रम एजेंडे के तहत हुई है जिसमें लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से संबंधित संसाधनों एवं अधिकार क्षेत्र को एक साथ जोड़ा गया है जो अधिक प्रभावी है। प्रतिवर्ष 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 16 दिवसों तक लोगों को महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ सक्रिय और जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जाता है। इसका स्लोगन है No E&cuse महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट हो और इस दिन यूनेस्को के द्वारा विश्व को नारंगी रंग में रोशन किया जाएगा।

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में यौन शोषण और उत्पीड़न,बलात्कार एवं बलात्कारोत्तर मानसिक और शारीरिक शोषण,तस्करी,अपहरण, अनैतिक देह व्यापार, घरेलू हिंसा,भावनात्मक शोषण,एसिड अटैक, डेटिंग दुरूपयोग, अंतरंग साथी की हिंसा, जबरन गैंगनोग्रफ़ी, सायबर क्राइम,छिपकर देखना (Stalking),ब्लेक मेल (Voyeurism) करना,ऑनर किलिंग इत्यादि को शामिल किया जाता है। समूचे विश्व में महिलाओं और लड़कियों के साथ किसी न किसी रूप में हिंसा अवश्य होती है जिसकी मात्रा देशों की विविधताओं के साथ कम या ज्यादा हो सकती है,लेकिन हर देश की महिला हिंसा को सहती है। अफ्रीका सहित कई देशों में संस्कृति के नाम पर महिलाओं का जेनांगहैडिकरण और ब्रेस्ट आयरनिंग जैसी भयावह अमानवीय प्रथाएं प्रचलित हैं। चीन में भी संस्कृति के नाम पर फुट बाध्यकरण (Foot Binding) महिलाओं पर सदियों से थोपा

व्यंग्य

अशोक गौतम

लेखक व्यंग्यकार हैं।

ते जब भी निकट भविष्य में किसी में भी दुहने की संभावनाएं देखते हैं तो उसके चरण कमलों के हो जाते हैं। तब उसे वे गैर मंजूरशुदा अहते में उसकी सेवा करवाने लाते हैं। वे गैर मंजूरशुदा साहित्य रचते हैं। गैर मंजूरशुदा अहते में गला तर करने बैठते हैं। हर मंजूरशुदा से उनका सैतीस का आंकड़ है। कल फिर वे अचानक गैरमंजूर शुदा अहते में बैठेदिखे, अपने तय कोने में। उन्हें बहुधा कोने ही पसंद है। चाहे साहित्य के हों या फिर गैर मंजूरशुदा अहते के। मैंने देखा कि उन्होंने कोई जकड़ रखा है। उनकी मापदूर किसीको उतनी पकड़ने में नहीं जितनी जकड़ने में है। गैर मंजूरशुदा ही सही , साहित्यकार हैं, सो, प्रकाशक, आलोचक, संपादक ही पकड़ेंगे। मेरी तरह श्रीमती के चरण तो पकड़ने से रहे। नीच से नीच गूस्सय को जो कहीं मुक्ति मिलती है तो केवल बीबी के चरणों में ही मिलती है।

मैंने अपने कबाड़ी की शर्ट के मेरी तरह तुड़े मुंडे कॉलर खड़े किए और दबे पांव उनके पास जा पहुंचा। मुझे देख वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। बस, जिसके वे चरणों को चूम रहे थे, उनके पाक से हाथ जोड़

एशियाई समाजवाद में है भारत की विदेश नीति की स्थिरता

यह भी एक संभावना है कि उनकी इस कल्पना के पीछे अमेरिका का कुछ संकेत रहा हो। क्योंकि सार्क में चीन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार शामिल थे। यह नीति एक प्रकार से चीन से भिन्न और पड़ोस के दक्षिण एशिया के देशों को एक मंच पर इकट्ठा कर चीन के मुकाबले खड़ा करने की नीति थी। इस नीति का भारत की सरकार ने, साम्यवादियों व लगभग सभी सदस्यीय दलों ने समर्थन दिया। यद्यपि हम समाजवादियों ने यह माना कि यह डॉ. लोहिया के भारत-पाक महासंघ के द्वारा गरीब व भारत के विभाजन की काली रेखा को कमजोर करने और आक्रामक चीन के मुकाबले एक ताकतवर मंच बनाने की भूमिका से हटने की शुरुआत है। जबकि सार्क के इस विचार ने दक्षिण एशियाई भूभाग में एक एकता का मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया था। हम लोगों ने दक्षेश देशों का सम्मलेन दिल्ली में आयोजित कर सार्क सिटीजन फोरम का गठन किया व उसके लिए काम शुरू किया था। परन्तु 1991 में स्व. नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सार्क से हटकर एक नई नीति की रचना की। श्लुक टू द ईस्टय की इस नीति के तहत पूर्वी एशिया याने चीन की तरफफिर दोस्ती के चरमे से देखना शुरू किया है। इसके कई कारण हो सकते हैं।

सैन्य शक्ति से तिब्बत पर कब्जा किया। पंचशील समझौते के दो साल बाद ही भारत की उत्तरी सीमा पर हमला कर भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा किया। इन सब में रूस की भूमिका लगभग एक मुकदर्शक व समर्थक जैसी बनी रही। इन घटनाओं से नाटो और सेंटो का प्रभाव कम हुआ। वियतनाम में सारे हथियारों के प्रयोग के बाद भी अमेरिकी पराजय के बाद अमेरिका और नाटो की भूमिका अविश्वसनीय और सीमित हुई। इक्कीसवीं सदी के आते-आते दुनिया ने नाटो और सेंटो से हटकर तथा यू.एन.ओ. से भी इतर अपनी अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार देशों के समूह बनाने शुरू किये। 1991 में स्व. नरसिंह राव की सरकार ने श्लुक टू द ईस्टय के नाम से एक नई विदेश नीति की शुरुआत की। उन्होंने पाकिस्तान से भिन्नता व सार्क संगठन की भारतीय विदेश नीति के बदलने की शुरुआत की। दरअसल 1980 के बाद सार्क की चर्चा (दक्षिण एशियाई देशों) शुरू हुई थी। इसके मूल में बांग्लादेश के विद्वान थे जिन्होंने दक्षिण एशियाई देशों के एक आर्थिक संगठन की कल्पना प्रस्तुत की। यह भी एक संभावना है कि उनकी इस कल्पना के पीछे अमेरिका का कुछ संकेत रहा हो। क्योंकि सार्क में चीन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार शामिल थे। यह नीति एक प्रकार से चीन से भिन्न और पड़ोस के दक्षिण एशिया के देशों को एक मंच पर इकट्ठा कर चीन के मुकाबले खड़ा करने की नीति थी। इस नीति का भारत की सरकार ने, साम्यवादियों व लगभग सभी सदस्यीय दलों ने समर्थन किया। यद्यपि हम समाजवादियों ने यह माना कि यह डॉ. लोहिया के भारत-पाक महासंघ के द्वारा गरीब व भारत के विभाजन की काली रेखा को कमजोर करने और आक्रामक चीन के मुकाबले एक ताकतवर मंच बनाने की भूमिका से हटने की शुरुआत है। जबकि सार्क के इस विचार ने दक्षिण एशियाई भूभाग में एक एकता का मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया था। हम लोगों ने दक्षेश देशों का सम्मलेन दिल्ली में आयोजित कर सार्क सिटीजन फोरम का गठन किया व उसके लिए काम शुरू किया था। परन्तु 1991 में स्व. नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सार्क से हटकर एक नई नीति की रचना की। श्लुक टू द ईस्टय की इस नीति के तहत पूर्वी एशिया याने चीन की तरफफिर दोस्ती के चरमे से देखना शुरू किया है। इसके कई कारण हो सकते हैं।

1.उस समय अमेरिका व चीन के बीच मित्रवत सम्बन्ध शुरू हो गए थे व व्यापारिक संबंध और चीन अमेरिका के आर्थिक व राजनैतिक सम्बन्ध भी पिघलने लगे थे।

अमेरिका ने अपना बाजार चीन के लिए खोला था। तथा चीन ने अमेरिकी कंपनियों को प्रवेश देना शुरू किया था। यह जुमला चल पड़ा था कि अब विदेश नीति व रिश्ते सरकारों या राजनीति नहीं वरन व्यापार तय करेंगे। 2.वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर लांदेन के हमले के बाद अमेरिका का मुख्य लक्ष्य लांदेन को मानना व अफगानिस्तान के तालिबानों को मिटना था। एक प्रकार से यह मुस्लिम कट्टरपन्थ व मुस्लिम आक्रामकता के खिलाफभी बाबरिक हमला था। स्व. नरसिंह राव भी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के बाद देश व विदेश में मुस्लिम समाज के निशाने पर थे। सम्भव है कि इसीलिए उन्होंने सेंटो से हटकर ईस्ट की ओर देखना शुरू किया है। लगभग एक दशक तक भारत की सरकारें इस नीति पर चली रहीं। परंतु जब चीनी आर्थिक सत्ता व आर्थिक साम्राज्यवाद से अमेरिका के लिए खतरा शुरू हुआ तो अमेरिका ने अपनी नीति को बदला। चीन ने अमेरिका के के उपभोक्ता बाजार पर कब्जा जमा लिया था। अपनी साहूकारी नीति से पैसा देकर नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश आदि देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। और वन बेल्ट वन रोडकी महत्वाकांक्षी योजना से अपने व्यापार को सड़क मार्ग से ईरान और यूरोप तक जोड़ने की योजना पर काम शुरू किया था। इस खतरे को समझ कर अमेरिका ने अपने बाजार व सहयोगी देशों के बाजार में चीन को प्रतिबंधित करना शुरु किया। चीनी विस्तार को फिर से रोकने की नीति शुरू की। भारत कभी भी अमेरिकी प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका है। जिस प्रकार अमेरिका की चीन के प्रति नीति बदलने से भारत भी पूर्व की ओर देखने लगा था उसी प्रकार बाद में अमेरिका को नजर से भारत ने पश्चिम की ओर देखना शुरू किया। इसके लिए कई कई देशों के कई संगठन बनायें जाने शुरू हुए। विदेश नीति में एक बदलाव आया कि विभिन्न विषयों के आधार पर देशों के समूह या संगठन बनाये जायें या जो बने उनमें शामिल हुआ जाए। यह एक प्रकार से दो ध्रुवीय दुनिया के विखंडन की शुरुआत थी। संचाई सहयोग के नाम से (एससीओ) नामक एक समूह बना जिसमें चीन नहीं था पर पाकिस्तान है। इस संगठन के सम्मेलन में हिस्सेदारी करने के लिए 9 वर्षों के बाद भारत के विदेशमंत्री श्री जयशंकर 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचे। यद्यपि यह शिरकत अभी बहुत प्राथमिक है। इसके चा दिन पूर्व याने 11 अक्टूबर 2024 को वियतनाम में एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों का सर्वाधिक नाकारात्मक

प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा है। भारत सरकार ने 1950 की निर्गुट नीति, फिर सार्क संगठन फिर, लुक टू द ईस्ट, फिर ब्रिक्स और अब दक्षिण एशिया के आगे जाकर दक्षिणी विश्व की चर्चा शुरू की है।

ब्रिक्स में भार, रूस, चीन और विश्व के दक्षिण के देश जिनमें साउथ अफ्रीका, किर्गिजस्तान आदि शामिल हैं को महत्व देना शुरू किया। उन्होंने अपने भाषण में पश्चिमी एशिया में शान्ति बहाल हो इसकी भी चर्चा शुरू की। याने विदेश नीति का केंद्र अब सार्क से हटकर कुछ पूर्वी एशिया के देशों की तरफदेखना शुरू किया। ग्लोबल साउथ का इस्तेमाल लेंटिन अमेरिका, अफ्रीका और ओसैनिया के गरीब और पिछड़े देशों के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति अस्थिरता और हड़तालों में घूमती है। जिसे अपने वास्तविक राष्ट्रीय हितों की या तो ठीक समझ नहीं है या फिर उनके प्रति गंभीर नहीं है।

पूर्वी एशिया के शिखर सम्मलेन के एक दिन पहले ही श्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में भारत आशियान ने बैठक को सम्बोधित किया था। उपर्युक्त घटनाओं से यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति तात्कालिकता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। 1950 के दशक में ही समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने एशियाई समाजवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने रंगून के सम्मलेन में एशियाई समाजवाद की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। वे चाहते थे कि एशिया के सभी देश समाजवाद के रास्ते को स्वीकार करें और एक सामूहिक नीति तैयार करें, जो अमेरिकी पूँजीवाद और नाटो के सैन्य वर्चस्व तथा रूस के साम्यवाद और सेंटो के वर्चस्व से हटकर हो। एशिया के देशा राष्ट्रीय सम्मत्ता, लोकतंत्र, समता और छोटी मशीन के आधार पर एशिया को समाजवादी बनाने की पहल करें। यह पूँजीवाद और साम्यवाद दोनों के आर्थिक और राजनैतिक वर्चस्व का विकल्प बने। अगर डॉ. लोहिया की विदेश नीति को तत्कालीन भारत सरकार ने स्वीकार किया होता और एशिया में समाजवाद की नीति को स्वीकार किया होता तो भारत की विदेश नीति में स्पष्टता और स्थिरता होती। एशिया अगर आज भी समाज की विचार व्यवस्था और सिद्धांतों पर एक गुट हो सके तो अफ्रीकी महाद्वीप व लेंटिन अमेरिकी देश एशिया के साथ होंगे। क्योंकि वे भी पूँजीवादी अमेरिका और यूरोप से शोषित हैं। शोषण भूक समाज की दुनिया के लिये यह एक ऐतिहासिक पहल हो सकती है।

फूल नोचवा प्रजाति को प्रमाण

कटाक्ष

श्याम यादव

लेखक व्यंग्यकार हैं।

अलसुबह मुंह अंधेरे उठने वाले उन तमाम बंधुओं भगिनियों को मेरा प्रणाम। प्रणाम इसलिए कि इस कुक्कुर्नी ठंड के मौसम में जब अलसुबह हम जयपुरिया रजाई में दुबके पड़े रहते हैं तब ये लोग बिना ठंड को परवाह किए हल्के अंधेरे में मुंह छिपाए,हाथों में पन्नी की थैली लिए हुए उन फूलों का शिकार करने निकल जाते हैं, जो बस सूरज निकलने से पहले खिल कर वातावरण को खुशनुमा बनाने



का प्रयास करते हैं। इन फूलों को तोड़ने, मतलब नोचने के पीछे इनका कोई आर्थिक हित नहीं होता। मतलब ये फूलों का कोई व्यापार व्यवसाय नहीं करते।

इन फूल नोचवा प्रजाति में केवल पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी होती है और जिस बेरहमी से ये खिलते हुए फूलों को डाली से नोचते है। उससे लगता है कि ये फूल तोड़ने की कला में पारंगत होते है। अब इनकी ये फूलों को नोचने को कला कहा जाय या विज्ञान ये अलग बहस का विषय हो सकता है। फूल नोचवा प्रजाति केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। आपकी बाउंड्री पर रखे गमले हो या बागिया के पौधे, इनकी निगाह से कोई नहीं बच पाता। अब इस बात पर अनुसंधान किया जा

है। चाहे बसाहट गरीबों वाली हो या अमीरी वाली। अंधेरे में भी इनकी आँखें इतनी तेज होती है कि ये उम्झू को भी कमजमा दे सकते है। ये प्रजाति फूल को दूर से ही निहार लेती है। आधे पौन घंटे के अलसुबह के इनके भ्रमण से इनका खुद का स्वास्थ्य तो ठीक रहता है, लेकिन ये पौधों का स्वास्थ्य खराब कर देते है। इतनी देर में इनकी वो थैली जो ये साथ ले कर चलते है भर जाती है ,लेकिन इस बीच वे 'अलीबाबा चालीस चोर की कहानी' के तरह उन फूलों की भी पहचान कर लेते है जो अगले दिन कली से फूल बनाने वाले होते है। यकीन न आए तो कभी अलसुबह उठकर इन फूल नोचवा प्रजाति से साक्षात्कार कर लींजिएगा।

चरण कमल बंदै पाठकाई

उठे और मुझे गैर मंजूरशुदा अहते के दूसरे कोने में ले गए। 'बंधु ! ये कौन? मैं'। सीधा प्रश्न पर आया। 'बस, यों ही समझ लो।' मतलब कोई प्रकाशक फांस लिया क्या ? कहीं की इंट कहीं का रोड़ा रचनाओं का कालजयी संग्रह प्रकाशित करवाने के लिए?' 'नहीं ! वे पूरे आतिश्यास से बोले। 'तो क्या साहित्य विभाग के कोई अफसर हैं? अफसरों की कृपा हो तो कूड़ा भी कालजयी हो सरकारी खरीद में मंजे से चला जाता है।' 'नहीं ! कहते हुए झिझक नहीं तो साफ हो गया कि वे सरकारी साहित्य विभाग के अफसर भी नहीं। मतलब वे सच बोल रहे हैं। 'तो क्या कहीं की इंट कहीं का रोड़ा रचनाओं की पेड समीक्षा के लिए कोई समीक्षक हैं?' 'कहा न ! नहीं यार ! तुम भी न ! लेखक की खाल उतार कर रख देते हो।' 'तो क्या कहीं की इंट कहीं को रोड़ा रचनाओं को प्रकाशित करवाने के लिए कोई संपादक पटा रहे हो?' 'नहीं।' तो ये बेतलब के अपरिचित कौन? क्योंकि जानता हूं जिससे तुम्हारा मतलब नहीं होता उसकी ओर तुम ओझी नजर से भी नहीं देखते। ऐसे में....' 'मेरा पाठक है यार ! उन्होंने सीना चीड़ा कर कहा तो मैं बेहेश होते होते बचा। 'पाठक? पाठक और लेखक का क्या नाता? लेखक और प्रकाशक का रिश्ता तो समझ में आता है, लेखक और संपादक का रिश्ता भी समझ

में आता है, लेखक और समीक्षक का रिश्ता भी कुछकुछ समझ में आता है, पर लेखक और पाठक का नाता? सबकुछ हजम कर जाने वाले को ये बात गुरु कुछ हजम नहीं हो रही, 'मैंने वो टुक कहा तो वे झल्लते बोले', समझते क्या नहीं यार ! पाठक है तो लेखक है। आजकल पाठक मिलता ही कहाँ है? तम अपने को चिड़िया का दूध लाने को कहेंगे तो पत्तक झपकते ले आऊंगा। पर माफ करना। पाठक लाने को कहेंगे तो मैं शर्मिदा हो जाऊंगा। हालांकि मैं शर्म फ्री जीव हूँ। कहीं भी किसी भी किसी भी स्तर की साहित्यिक गाँछ में चले जाऊँ। साहित्यिक गाँछों में सब कुछ होता है, चाय होती है, समोसा होता है, लंच भी कभी कभार हो जाता है। ऑन लाइन पारिश्रमिक भी कभी कभार खाते में आ ही जाता है। जितना अपने जाने का किराया भरो वह भी हो जाता है। पर गाँछियाँ में नहीं मिलता तो बस, पाठक नहीं मिलता। खुशनसीब होते हैं वे साहित्यकार जिनके पास साहित्य के अतिरिक्त पाठक भी होते हैं।'पाठक' मैंने न की मुदा मैं अपने कंधे उकचाए तो वे बोले, 'तुम क्या समझो पाठक की टू बेली ! सच्चे लेखक नहीं हो न। साहित्यकार होने के लिए पहली शर्त साहित्य नहीं, साहित्य रचने से पहले उसके साहित्य के पाठक होती है। पाठक है तो प्रकाशक है, पाठक है तो संपादक है, पाठक है तो समीक्षक है। जो पाठक नहीं होगा तो प्रकाशक क्या करेगा ? जो पाठक नहीं होगा तो अखबार कहाँ जाएगा?'

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)



मदरसे इस्लामी सिद्धांतों और प्रथाओं के साथ-साथ मुख्यधारा की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। अधिकांश मदरसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पाठ्यक्रम का पालन भी करते हैं। मदरसा अधिनियम उत्तर प्रदेश में इन संस्थानों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है जो पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करता है और निर्धारित करता है और सभी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। यह अधिनियम राज्य सरकार को मदरसा शिक्षा को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति भी देता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इस अधिनियम को पूरी तरह रद्द कर दिया था कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। साथ ही यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है। इसके अलावा एसआर बोम्पई बनाम भारत संघ (1994) में फैसला सुनाया था कि धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम ने छात्रों के लिए इस्लाम का अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया है और अधिक आधुनिक विषयों को वैकल्पिक बना दिया गया है। इसने माना कि राज्य धर्म के आधार पर शिक्षा प्रदान करके भेदभाव नहीं कर सकता है।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि यह अधिनियम आधुनिक विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित करके संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम के तहत फाजिल और कामिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करने की बोर्ड की शक्तियां क्रमशः स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के बराबर-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (यूजीसी अधिनियम) के साथ संघर्ष करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने तीन मुख्य आधारों पर उच्च न्यायालय के फैसले को दखिनार किया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बुनियादी शिक्षा परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। संवैधानिक संशोधनों

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।



सा रे जमाने में तमाम तरह के जमाने भर के विवाद है। जिसके चलते परस्पर हिंसा, मनुष्युघात और पारिवारिक रंजिश के अनगिनत मामले कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विचाराधीन है। हालांकि पीड़ित पक्ष को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है, लेकिन वह अपर्याप्त होकर सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान नहीं कर पाती। अनेक मामले ऐसे हैं जिनमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी अंतिम न्याय की प्रतीक्षा करती रहा करती है। नगरिकों का एक वर्ग विलंबित न्याय के दौर में त्वरित न्याय हेतु अनपेक्षित कदम उठाते भी देखा गया है। खैर, अब विवादों को तो जड़ मूल से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन विवाद कम होने की दिशा में तो कुछ सोचा जा सकता है।

इस संदर्भ में क्या ही बेहतर हो यदि विवादित मुद्दा सामने आने पर आदमी अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर विचार करें। वैसे यह बात एक परिकल्पना लग सकती है, लेकिन इसका व्यावहारिक महत्व अनुमान से कहीं बहुत ज्यादा होगा। दरअसल अधिकांश विवादों की जड़ में एकतरफा सोच विचार ही वह कारण बन जाता है जब कोई बात तूल पकड़ लेती है। इसके चलते दोनों ही पक्ष मानसिक दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। जिसका सीधे तौर पर नतीजा यह होता है कि दोनों ही पक्ष अपने-अपने क्षेत्र में अपनी-अपनी कार्यक्षमता को खोने लगते हैं। समाज में ऐसे अनगिनत

पर्यावरण

उपेन्द्र शंकर

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

जलवायु संकट से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 16 नवंबर 2024 को केरल के वझाचल से अथिरापिള്ളी तक, पांच किलोमीटर के क्षेत्र में, 'जलवायु मार्च 2024' का आयोजन किया गया। 'पीपुल्स क्लाइमेट एक्शन, केरल' और 'चालाकुडी रिवर प्रोटेक्शन फोरम' के संयुक्त नेतृत्व में इस जलवायु मार्च का आयोजन किया गया था।

16 नवंबर को 'रिवर रिसर्च सेंटर' के संस्थापक और प्रेक व्यक्तिव डॉ. लता अनंथा का स्मृत-दिवस भी है। वैज्ञानिक डॉ. लता का, जिन्होंने मुक्त प्रवाह वाली नदियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, 2017 में एक साल से अधिक समय तक कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया। उनकी उज्ज्वल यादों को श्रद्धांजलि देते हुए, डॉ. लता की 7वीं पुण्यतिथि पर ही इस 'जलवायु मार्च' का आयोजन किया गया था।

यात्रा की सुबह करीब 10 बजे विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के छात्र, केरल के विभिन्न हिस्सों से पर्यावरण कार्यकर्ता, कला, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, मौसम विशेषज्ञ और आम जनता वझाचल पहुंचे और लता स्मृति सभा का आयोजन किया। पर्यावरण कार्यकर्ता और 'नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स' (एनपीएम) के राष्ट्रीय संयोजक सीआर नीलकंदन ने समारोह की अध्यक्षता की और 'जलवायु मार्च 2024' के महासचिव एसपी रवि ने स्वागत किया।

केरल में पहला 'जलवायु मार्च' 2015 में आयोजित किया गया था, जब लोगों ने वझाचल से अथिरापिള്ളी तक मार्च किया था। मार्च के महासचिव रवि ने बताया यह चालाकुडी 'नदी बेसिन की सुरक्षा के लिए अथिरापिള്ളी आंदोलन की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था।' 'वर्ष 2016 से केरल नियमित रूप से चरम जलवायु घटनाओं का सामना कर रहा है। 2016 में, हमारे पास सूखा था, उसके बाद 2018 और 2019 में बाढ़ आई और फिर बड़े पैमाने

मदरसा अधिनियम - 1

मदरसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मदरसों जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक शिक्षा प्रदान करने और अपना प्रशासन संभालने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों पर रोक लगाने वाले उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को मंगलवार को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए पूरे अधिनियम को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का सभी वर्गों ने स्वागत किया है।

का परीक्षण बुनियादी संरचना सिद्धांत के खिलाफ किया जाता है, न कि एक सामान्य विधान के खिलाफ।

अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) के अपने फैसले का हवाला देते हुए इसे रेखांकित किया, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन से संबंधित था। इसे इंदिरा गांधी को चुनाव में भाग लेने से अयोग्य ठहराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को उलटने के लिए लागू किया गया था। संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के लिए संशोधन को चुनौती दी गई थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि, यह तर्क कि संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन करता है, एक साधारण कानून की वैधता निर्धारित करने के लिए बहुत अस्पष्ट और अनिश्चित था। मदरसा अधिनियम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए एक कानून को रद्द करने के लिए, इसे संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेदों) को व्यक्त करने के लिए पता लगाया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य मदरसों को नियमित कर सकता है, जब तक विनियमन उचित और तर्कसंगत है। राज्य प्रशासन को संभालने के अपने अधिकारों का उल्लंघन किए बिना अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षा के पहलुओं को विनियमित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मदरसा अधिनियम शैक्षणिक संस्थानों को उनके अल्पसंख्यक चरित्र से वंचित किए बिना ऐसा कर सकता है। न्यायालय ने संविधान में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 का भी उल्लेख किया जो राज्यों और केंद्र दोनों को शिक्षा के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है। इसमें कहा गया है कि इसको व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। इसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान शामिल होने चाहिए। सन्



2014 में सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 21 ए की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2006 (आरटीई अधिनियम) अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होना चाहिए। यह उनके अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट कर सकता है। मदरसा अधिनियम मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय का उल्लेख किया और कहा कि उच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए कानून को निरस्त करके गलती की थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि मदरसों जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक शिक्षा प्रदान करने और अपना प्रशासन संभालने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मदरसा अधिनियम की धारा 9 का एक हिस्सा जो बोर्ड को कामिल और फाजिल पाठ्यक्रम पूरा करने वालों को पाठ्यक्रम लिखने, परीक्षा आयोजित करने और डिग्री देने की अनुमति देता है, यूजीसी अधिनियम के विपरीत है। यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के तहत, केवल वे विश्वविद्यालय ही डिग्री प्रदान कर सकते हैं जिन्हें केंद्र या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है या जिन्हें यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय माना गया है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय ने धारा 9 के एक भाग को निरस्त कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ताजा फैसले में मदरसा अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि यह राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है। यह

सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययन करने वाले छात्र योग्यता का स्तर प्राप्त करें जो उन्हें समाज में प्रभावी ढंग से भाग लेने और आजीविका कमाने की अनुमति देगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21-ए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के साथ सुसंगत रूप से पढ़ा जाना चाहिए। राज्य सरकार की मंजूरी से मदरसा शिक्षा बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान अपने अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट किए बिना आवश्यक मानक की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करें।

इसके अलावा, मदरसा अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर है और सूची तीन की प्रविष्टि 25 तक इसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन न्यायालय ने यह भी माना कि मदरसा अधिनियम के प्रावधान जो उच्च शिक्षा की डिग्री को विनियमित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि फाजिल और कामिल असंवैधानिक हैं क्योंकि वे यूजीसी अधिनियम के साथ संघर्ष में हैं। इसे संविधान की सूची प्रथम की प्रविष्टि 66 के तहत अधिनियमित किया गया है। इस फैसले के साथ, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को भी उलट दिया, जिसने मदरसा अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21-ए का उल्लंघन करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (यूजीसी अधिनियम) की धारा 22 का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक घोषित किया था।

(शेष अगले कॉलम में)

अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर भी सोचिए...

इस संदर्भ में क्या ही बेहतर हो यदि विवादित मुद्दा सामने आने पर आदमी अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर विचार करें। वैसे यह बात एक परिकल्पना लग सकती है, लेकिन इसका व्यावहारिक महत्व अनुमान से कहीं बहुत ज्यादा होगा। दरअसल अधिकांश विवादों की जड़ में एकतरफा सोच विचार ही वह कारण बन जाता है जब कोई बात तूल पकड़ लेती है। इसके चलते दोनों ही पक्ष मानसिक दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। जिसका सीधे तौर पर नतीजा यह होता है कि दोनों ही पक्ष अपने-अपने क्षेत्र में अपनी-अपनी कार्यक्षमता को खोने लगते हैं। समाज में ऐसे अनगिनत लोग होंगे जिनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अंतिम रूप से न्याय पाने की प्रयासों में ही गुजर गया।

लोग होंगे जिनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अंतिम रूप से न्याय पाने की प्रयासों में ही गुजर गया।

ऐसी स्थिति स्वाभाविक रूप से आदमी को अस्थिर मनोवृत्ति की ओर धकेल दिया करती है। इसका प्रभाव सामाजिक परिवेश में नकारात्मक रूप से पड़ता है। जो प्रकारांतर से समाज एवं राष्ट्र के विकास क्रम को बाधित करता है। निश्चित रूप से यदि आदमी अपने सोच विचार को प्रतिद्वंदी की भावना से देखें, तो काफी हद तक विवादों को सुलझ जाने के आसार बनने लग जाते हैं। वर्तमान दौर में तमाम तरह के दीवानी मुकदमे पारिवारिक रिश्तों की मान मर्यादा को दांव पर लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में परस्पर नजदीकी रिश्तों में भी आत्मीयता का भाव विलुप्ति की कगार पर दिखाई देता है। आजकल तो खून के रिश्तों में भी रिश्ता निभाने की गारंटी नहीं मानी जा



सकती।

दरअसल जब दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवादित स्थिति बन जाती है, यह निश्चित है कि किसी एक का पक्ष ही सही होगा। या फिर उनके बीच किसी प्रकार की गलतफहमी होगी या वे परस्पर अविश्वास की भावना से भरे होंगे। ऐसी स्थिति में बीते दौर में स्थानीय सर्वमान्य प्रबुद्धजनों के समूह से विवादित स्थिति का निराकरण कराया जाता रहा था। तब न्याय सस्ता एवं सुलभ तो था ही लेकिन त्वरित निर्णय का भी कारण बना करता था। हालांकि उनके कार्यक्षेत्र का भी एक सीमित दायरा था, लेकिन जो भी था वह कारगर था। तब के जमाने में 'आंख की शर्म' पाली जाती थी। प्रतिष्ठितों की प्रतिष्ठा निर्विवाद रहा करती थी। लेकिन बदलते दौर में सब कुछ बदल गया।

इन तमाम सन्दर्भों में आम आदमी को महान धर्मग्रंथ रामायण और महाभारत के तमाम पात्रों की भूमिका पर विचार कर लेना चाहिए। इनका धार्मिक ही नहीं अपितु व्यावहारिक महत्व भी है। हर कोई इन ग्रंथों के प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण से भलीभांति परिचित है। व्यावहारिक रूप से आदमी के निजी, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में आने वाली तमाम विकट स्थिति के दौर में आदमी को इन ग्रंथों के प्रमुख पात्रों की भूमिका से बहुत कुछ सीख मिल सकती है। एक पल के लिए आदमी को यह सोच लेना चाहिए कि यदि वह किसी विवाद में उलझा है तो उसके अंतर्गमन में कौन सा पात्र स्थापित हो गया है? ऐसे में हम स्वयं अपने आपको पहचानने की मुद्रा में आ जाएंगे। हम स्वयं सही और गलत का निर्णय ले लेंगे। फिर विवाद रह ही कहां जाएगा?

एक पल, केवल और केवल एक पल, एक पल में ही अपनी स्थिति का भान हो जाएगा। निश्चित रूप से जब हम किसी बिंदु पर आत्म स्वीकृति पा लेते हैं, फिर कहीं से कहीं तक विवादित स्थिति आती ही नहीं है।

जलवायु मार्च : केरल को बचाने की कोशिश

केरल में पहला 'जलवायु मार्च' 2015 में आयोजित किया गया था, जब लोगों ने वझाचल से अथिरापिള്ളी तक मार्च किया था। मार्च के महासचिव रवि ने बताया यह चालाकुडी 'नदी बेसिन की सुरक्षा के लिए अथिरापिള്ളी आंदोलन की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था।' 'वर्ष 2016 से केरल नियमित रूप से चरम जलवायु घटनाओं का सामना कर रहा है। 2016 में, हमारे पास सूखा था, उसके बाद 2018 और 2019 में बाढ़ आई और फिर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं जहाँ तत्काल और पर्याप्त जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में हमने डॉ. लता की सातवीं पुण्यतिथि को जलवायु मार्च के रूप में आयोजित करने के बारे में सोचा।'

पर भूस्खलन हुआ। हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं जहाँ तत्काल और पर्याप्त जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में हमने डॉ. लता की सातवीं पुण्यतिथि को जलवायु मार्च के रूप में आयोजित करने के बारे में सोचा।'

सरकार जलवायु संकट पर हर चीज को दोष देती है, लेकिन शमन के लिए कुछ नहीं करती है। रवि ने कहा, 'सभी आपदाएँ अत्यधिक वर्षा या चरम जलवायु घटनाओं के कारण नहीं होती हैं। इन आपदाओं में भूमि उपयोग परिवर्तनों की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।' वर्ष 2018 की विनाशकारी बाढ़ कई कारणों से आई थी, जिसमें पश्चिमी घाट में भूमि उपयोग में बदलाव और मध्यभूमि में धान की खेती शामिल है। बांधों ने भी इसमें भूमिका निभाई और आपदा प्रबंधन तंत्र की विफलता भी हुई। रवि ने कहा, 'इन सभी का सम्मिलित प्रभाव बड़े पैमाने पर बाढ़ था, जिसने आपदा की भयावहता को कई गुना बढ़ा दिया। इन सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है।' पश्चिमी घाट सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है।

पश्चिमी घाट क्षेत्र में तापमान वृद्धि मध्यभूमि से अधिक बताई जाती है और तापमान या वर्षा पैटर्न में एक छोटा सा बदलाव भी जैव-विविधता को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। रवि ने कहा, 'केरल पश्चिमी घाट के संरक्षण में है,

इसके बिना केरल, जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में नहीं रह सकता, लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिमी घाट के इस महत्वपूर्ण महत्व को स्वीकार नहीं किया जाता है।'

तटीय क्षेत्र में कई स्थानों पर लगातार तूफानी लहरें और ज्वारीय बाढ़ देखी जा रही है। 'उच्च जनसंख्या घनत्व वाला पूरा तटीय क्षेत्र बेहद संवेदनशील हो गया है और हम नहीं जानते कि कब कोई बड़ी आपदा आ जाएगी।' केरल में जलवायु कार्यकर्ता चाहते हैं कि उन क्षेत्रों को विशेष महत्व

दिया जाए जहाँ अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है। वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्थानीय स्वशासन स्तर से लेकर सभी सरकारी परियोजनाओं की जलवायु संकट के संबंध में जांच की जाए।'

शमन और लचीलापन निर्माण के लिए विशिष्ट गतिविधियों की आवश्यकता है, यह अस्पष्ट नहीं हो सकता और केवल राज्य-स्तरीय कार्य योजना रखने की बजाय, हमें इसे स्थानीय स्तर पर विभाजित करना पड़ सकता है। 'केरल

स्थानीय प्रशासन संस्थान' (KILA) ग्राम पंचायतों के लिए जलवायु पर लचीली योजनाएँ विकसित कर रहा है, लेकिन पता नहीं कि इसका कितना हिस्सा जमीनी स्तर पर पहुँचा है,' रवि ने कहा।

स्थानीय निकाय, समुदाय के स्तर पर भागीदारी और युवाओं की भागीदारी इस दृष्टिकोण के लिए बुनियादी है। रवि के मुताबिक, 'अभी कई जगहों पर मानसून की बारिश की निगरानी हो रही है, जिसे राज्य की कार्ययोजना में शामिल किया जाना चाहिए और कार्रवाई करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। युवाओं को इसमें सबसे आगे रहना होगा। इन चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। जिस तरह से इसे पढ़ाया जा रहा है, वह ज्यादातर सतही है। हमेशा की तरह चलने वाला परिदृश्य अब संभव नहीं है।'

वर्ष 2022 में केरल ने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना को संशोधित किया था, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अपने कमजोर भौगोलिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की पहचान की गई थी, लेकिन जलवायु कार्यकर्ताओं को लगता है कि जमीन पर पर्याप्त काम नहीं किया जा रहा है।

जलवायु संकट पर जागरूकता पैदा करने और कार्रवाई को गति देने के लिए 'जलवायु मार्च 2024' के आयोजक कम-से-कम 10 वर्षों की अवधि के लिए पूरे राज्य में एक अभियान विकसित करने की योजना बना रहे हैं। यह कार्यक्रम 29 वें 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन' ('कोप29') के साथ भी मेल खाता है, जो इन दिनों (11 से 22 नवंबर2024 तक) अजुर्बैजान के बाकू में चल रहा है। (संप्रेस)

भौरा में आधार सेवाओं का संकट, नागरिकों को उठानी पड़ रही भारी परेशानी

आधार कार्ड बनाने व अपडेट कराने परेशान हो रहे लोग

बैतूल/भौरा। शहर का आधार केन्द्र बंद है। आधार अपडेट कराने या बनाने के लिए लोगों को शाहपुर या बैतूल जाना पड़ता है। यहां भी एक दिन में आधार अपडेट या आधार नहीं बनने से लोगों को माथूस लौटना पड़ रहा है। दरअसल भौरा का एकमात्र आधार केंद्र पिछले 6 माह से से बंद पड़ा है। इस वजह से ग्रामीणों को न केवल समय और पैसे की बर्बादी झेलनी पड़ रही है, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से भी वंचित रहना पड़ रहा है। भौरा के आधार केंद्र को 6 माह पहले बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके सुपरवाइजर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। आधार के अभाव में भौरा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों

के लोगों को आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार कराने के लिए 10 किमी दूर शाहपुर या 50 किमी दूर बैतूल जाना पड़ता है। वहां की लंबी कतारों और सीमित संसाधनों के कारण कई बार उन्हें बार-बार आना-जाना पड़ता है। इन्हीं आधार केन्द्रों पर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आकर आधार में सुधार करवाते है। जिससे आधार केन्द्रों पर अत्याधिक भीड़ हो रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि सुबह से ही आधार अपडेट कराने के लिए लोग केन्द्र पर लोग पहुंच जाते है। लोगों ने बताया कि भीड़ को वजह से आधार में सुधार व अन्य काम कराने के लिए पूरा दिन लग जाता है।

आधार केंद्र बंद होने से लौट रहे लोग-ग्राम झापड़ी के सुरेश यादव ने बताया कि वह अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए भौरा पहुंचे, लेकिन आधार सेंटर बंद होने के कारण उन्हें शाहपुर जाना पड़ा। बच्चों के स्कूल के लिए आधार कार्ड जरूरी है। लेकिन हर बार इतनी दूरी तय करना और दिन भर कतार में खड़े रहना मुश्किल है। आज भी काम नहीं हो पाया। सोमवार को फिर आना पड़ेगा। इसी तरह ग्राम भौरा की विधा बाई, जो अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक कराने के लिए शाहपुर गई थीं, ने बताया हम बुजुर्ग लोग इतनी दूर आ-जा नहीं सकते। भौरा में केंद्र होता तो हमें यह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती।

आधार के बिना नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ - भौरा और आसपास के गांवों में आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है। लेकिन जिन लोगों के आधार कार्ड अपडेट नहीं हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए आधार अपडेट कराना खासा मुश्किल हो गया है। ग्राम हांडीपानी के सुखराम चौहान ने बताया, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। इसे अपडेट कराने के लिए मुझे तीन बार शाहपुर जाना पड़ा। वहां लंबी कतारों और अधिक भीड़ के कारण हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा।

लोगों ने कहा, भौरा में शुरू

किया जाये आधार सेंटर- भौरा और आसपास के गांवों के निवासियों ने प्रशासन से जल्द से जल्द आधार केंद्र को पुनः चालू करने की मांग की है। स्थानीय नागरिक अर्पित तिवारी ने कहा, आधार कार्ड आज के समय में हर सरकारी योजना का आधार है। इसके बिना न तो सरकारी लाभ मिल पा रहा है और न ही अन्य जरूरी काम हो पा रहे हैं। भौरा में आधार सेवाओं की बहाली समय की मांग है। आधार केंद्र के बंद होने के कारण हजारों लोग परेशान हैं। प्रशासन से अपेक्षा है कि वह इस समस्या को प्राथमिकता देकर जल्द समाधान निकाले। ऐसा होने पर न केवल लोगों का आर्थिक और समय का नुकसान रुकेगा, बल्कि सरकारी

योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा।
सुपरवाइजर को कर दिया था ब्लैकलिस्ट- भौरा और आसपास के गांवों के निवासियों को आधार सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार केंद्र जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके। भौरा का आधार केंद्र पिछले छह माह से बंद है क्योंकि इसके सुपरवाइजर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। यह केंद्र पहले प्रोजेक्ट सीएसी के माध्यम से संचालित हो रहा था, जो अब बंद हो चुका है। अब इस

इनका कहना -
पुराने आधार केंद्र की आईडी भी बंद हो चुकी है। चूंकि प्रोजेक्ट सीएसी से हटकर इसे ई-गवर्नेंस के अधीन किया गया है, इसलिए संचालन रुका हुआ है। नए केंद्र के लिए फॉर्म जमा कर दिया गया है और जैसे ही ई-गवर्नेंस से स्वीकृति प्राप्त होगी, आधार केंद्र को पुनः चालू कर दिया जाएगा।
- **कमलेश रघुवंशी, प्रबंधक, सीएसी बैतूल**

परियोजना को जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा हैंडओवर लिया जा रहा है और आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इधर कांग्रेस का दावा – कांग्रेस का संघर्ष रंग लाया, अब निजी हाथों में नहीं जाएगा जिला अस्पताल

बैतूल। पीपीपी मोड पर मेडिकल कालेज बनाने और उसके लिए सरकारी जिला अस्पताल को भी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में देने के फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि लौट कर कम अक्ल घर पर आए। यह बात कहते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता मोनू वाघ ने कहा बैतूल जिले में जिला अस्पताल को पीपीपी मोड के मेडिकल कालेज के लिए प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिए जाने का जिला कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया था। उनका कहना है कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत वाग्दे के नेतृत्व में जिले के कांग्रेसियों ने 8 अगस्त को बरसात में भीगते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल और ज्ञापन देकर इस मामले को आम जनता के बीच लेकर गई थी। इसके बाद भी हर मौके पर इस मुद्दे को उठाना गया। इससे आम जनता में सरकारी अस्पताल के निजी हाथों में जाने का आंतरिक आक्रोश फैल गया। बैतूल सहित अन्य जिलों में भी विरोध शुरू हुआ। इसी का नतीजा है कि सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा और सरकारी अस्पताल को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला बदलना पड़ा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि सरकार यह भी बताए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कब तक अपना स्वयं का अस्पताल बनाएगा और उक्त अस्पताल में आम जनता के निःशुल्क इलाज के लिए कितने बेड उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश सरकार के साथ बैतूल के सांसद सहित सभी विधायक जनता को जवाब दे।

विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग आज से प्रारंभ

बैतूल। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस संबंध में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी मोनिका चौधरी ने बताया कि इस बार का युवा महोत्सव बेहद खास और अलग होगा। इस बार की जो थीम है वह काफी नई और यूनिक है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के थीम पर आधारित चार स्टेज में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें युवा द्वारा माय भारत पोर्टल पर जाके 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रतिभाग किया जा सकता है।15 से 29 वर्ष के युवा इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। पहले चरण में विकसित भारत की थीम पर ऑनलाइन क्रिज कंपटीशन का आयोजन माय भारत पोर्टल पर होगा। इसमें से चुने गए प्रतिभागी दूसरे चरण में ऑनलाइन निबंध लेखन में भाग लेंगे। तीसरे लेवल पर स्टेट चैंपियनशिप भोपाल में और चौथी और आखिरी चरण में नेशनल चैंपियनशिप नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री की मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा यंग माइंड को अपने देश की संस्कृति, इतिहास और सभ्यता से जोड़ना होगा और साथ ही साथ युवाओं से संवाद कर उनके विचार को प्रमुखता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर साझा करना होगा। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान 11 और 12 जनवरी 2025 को आयोजित होगा। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत मंडपम में 3 हजार युवा नेताओं के साथ संवाद करेंगे। इन 3 हजार युवा नेताओं में से 1500 प्रतिभागियों का चयन विकसित भारत चैलेंज के माध्यम से माय भारत प्लेटफ़ॉर्म पर किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को पहचानना और उसे प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें विकसित भारत के लिए अपने विचार साझा करने का एक मंच मिल सके। धनंजय सिंह ठाकुर ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य आकर्षण यह होगा कि युवा सीधे प्रधानमंत्री के साथ संवाद कर सकेंगे और भारत के भविष्य के लिए अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे राजनीति और सामाजिक जीवन में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

1 दिसम्बर को होगा दिवाली गोठान महोत्सव

बैतूल। सर्व आदिवासी समाज के तत्वाधान में आदिवासी सामुदायिक मंगल भवन में रविवार 24 नवंबर को बैठक आयोजित की गई। बैठक में 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार को जिला स्तरीय दिवाली गोठान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। समाज के अविनाश धुर्वे ने बताया कि जिला मुख्यालय के शिवाजी ऑडिटोरियम में 1 दिसंबर को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक दिवाली गोठान महोत्सव में आदिवासी समाज की संस्कृति रीति रिवाज, परंपरा देखने को मिलेगी। दिवाली गोठान महोत्सव में पूरे जिले से गोंड गायकी (ठाडिया) समुदाय के जाने माने 200 से अधिक कलाकार गोठान में गायकी नृत्य की प्रस्तुति देंगे। गोंडी डंडार की लगभग दो दर्जन टीमों के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। कोरूक आदिवासी समुदाय की गली नृत्य की टीमें भी महोत्सव में शिरकत करेंगी। अंकित कुमरे ने बताया कि दिवाली गोठान सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत पडापेन ठाना सदर से होगी एवं गोठान महोत्सव का आयोजन रानी दुर्गावती ऑडिटोरियम में किया जाएगा। विशाल धुर्वे ने बताया कि इस गोठान सांस्कृतिक महोत्सव में बैतूल जिले के अलावा अन्य जिलों के भी आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। कार्यक्रम में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी गई है। इस बैठक में आकास संगठन जिला अध्यक्ष शंकर सिंह आहके, युआवि संगठन जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह इवने, अविनाश धुर्वे, अंकित कुमरे, विशाल धुर्वे, अनिल परते, रामदास उड्के, उमेश परते,प्रकाश उड्के, करण चढोकार सहित अन्य सामाजिक बन्धु उपस्थित थे।

स्कूल न जाने वाली बालिकाएं होती हैं ज्यादा अपराध का शिकार : एसपी कमला जोशी



बैतूल। सीएम राइस स्कूल बैतूलबाजार में पुलिस विभाग के प्रयास एक कोशिश टीम एवं प्रत्याशा फाउंडेशन ने बालिका जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों एवं बालिकाओ से जुड़े अपराधों से बचाव व जानकारी दी गई। कार्यक्रम में एसपी कमला जोशी, शाहपुर एसडीओपी मयंक तिवारी बैतूल बाजार थाना प्रभारी रंजना धुर्वे, यातायात

प्रभारी गजेंद्र केन, साइबर सेल प्रभारी नवीन सोनकर उपस्थित थे। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद नवांकुर संस्था प्रत्याशा फाउंडेशन से तूलिका पचौरी, निमिषा शुक्ला, प्रमिला धोत्रे, आशीष पचौरी एवं आशीष कोकने, प्रदीपन संस्था की ओर से रेखा गुजरे एवं दीपमाला खातरकर, मीरा एंथोनी, मध्यप्रदेश जन अभियान की ओर से संभाग समन्वयक कौशलेश तिवारी एवं जिला समन्वयक प्रिया चौधरी, महिला बाल

महाराष्ट्र चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर आमला के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न



बैतूल/आमला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। स्थानीय विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनपद चौक आमला पर जश्न मनाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन एवं झारखंड चुनाव समेत अन्य राज्यों में संपन्न उप चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में मातृशक्ति, युवा साथियों कृषक बंधुओं, बहन-बेटियों और जागरूक मतदाता बंधुओं ने दिखा दिया कि वो भाजपानीत महायुति के विकास के साथ है। ऐतिहासिक परिणाम भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के कठोर परिश्रम एवं भाजपानित महाराष्ट्र सरकार समेत संपूर्ण देश में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रतिफल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामो से साफ दिखता है की कांग्रेस की झूठ की दुकान और उसके सहयोगियों के भ्रष्टाचार को जनता ने सिर से नकारा है। ये जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, विकास की जीत है।

स्वामी रामदेव के शिष्य आएंगे बैतूल

13, 14 और 15 दिसंबर को शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम में होगा शिविर

बैतूल। योगऋषि स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन में बैतूल में दिसंबर माह में विशाल योग आरोग्य शिविर लगने जा रहा है। इसमें योगपीठ हरिद्वार से स्वामी परमार्थ देव जी उपस्थित रहेंगे। इस शिविर में योग के अलावा आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सभी बीमारियों का उपचार होगा। यह जानकारी भारत स्वाभिमान न्यास और पतंजलि योग समिति के राज्य प्रमुखव्दय करण सिंह और डॉ.पुष्पांजलि शर्मा ने दी। भोपाल से बैतूल तैयारियों का जायजा लेने आए इन लोगों ने अनुराग टेंट हाउस राजा भोज मार्ग में आज सुबह पंतजलि की जिले भर की टीम की बैठक लेकर जानकारी दी। 24 दिसंबर रविवार सुबह 11 बजे दीप प्रज्वलित कर इस बैठक का शुभारंभ किया गया। इसमें भारत स्वाभिमान न्यास के राज्य प्रभारी करण सिंह, पतंजलि योग समिति की राज्य प्रभारी डा पुष्पांजलि शर्मा, पतंजलि किसान समिति के राज्य प्रभारी कमलेश गौर, भारत स्वाभिमान न्यास के सहराज्य प्रभारी आवठे, युवा भारत के राज्य प्रभारी लखन के अलावा शिविर



आयोजन समिति से जुड़े सुनील द्विवेदी, बलराम जसूजा, संजय शुक्ला, दीपक पाल के अलावा भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी सुनील कुबड़े, विमल दुबे, हितेश पटेल, संगीता अवस्थी, विनोद परिहार आदि शामिल थे। इस बैठक में राज्य के प्रभारियों के अलावा जिले भर के समिति के सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में बताया गया कि आगामी माह के 13, 14 और 15 दिसंबर को तीन दिवसीय योग-आरोग्य शिविर लगेगा। इसमें सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पतंजलि योग समिति के केंद्रीय प्रभारी स्वामी डा

परमार्थ देव के सानिध्य मार्गदर्शन योग व ध्यान होगा। इसके बाद सुबह 9 बजे से 12 बजे तक फिर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आरोग्य शिविर लगेगा। इस आरोग्य शिविर में सभी बीमारियों का उपचार आयुर्वेद, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से तीनों दिन किया जाएगा। इसके अलावा स्वामी जी का स्कूलों में, आठनेर में कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से पतंजलि के योग साधक आएंगे। राज्य स्तरीय

सम्मेलन भी होगा। इसके साथ ही योग गुरुओं का सम्मान होगा, वहीं योग साधकों और छात्र छात्राओं को हर्द्वार से आए प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे। रविवार की इस बैठक में श्रीमती तरुणा द्विवेदी, रत्नमाला कुबड़े, चंदा भूभरकर अरुणा पाटनकर, रीना इवने मानी सोलंकी, प्रीति साहू, दिनेश, नवनीत वर्मा, राजेश कोडले, बल्लू गुप्ता, संतोष राठौर, गणेश नरवरे, कृष्णराव झरबड़े राजेश पंडोले, विमल दुबे, नायक, सुनील मेसरे, शिवपाल, सतीश पाल, निखितकर, पंजाबराव अड्लक आदि मौजूद थे।

मेडिकल कॉलेज बनेगा लेकिन पीपीपी मोड पर नहीं जाएगा जिला अस्पताल

बैतूल विधायक ने मुख्यमंत्री-स्वास्थ्य मंत्री का आभार माना

बैतूल। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के विशेष प्रयासों से जिला मुख्यालय बैतूल में स्वीकृत हुए मेडिकल कॉलेज में जिला अस्पताल को भी पीपीपी मोड पर सौंपने का प्रावधान था। मेडिकल कॉलेज की स्थापना के दौरान जिला अस्पताल को पीपीपी मोड पर देने की बजाए उसका स्वरूप यथावत रखने के लिए बैतूल विधायक श्री खण्डेलवाल द्वारा म.प्र.के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री - स्वास्थ्य मंत्री से भेंट कर मांग की गई थी। अखिरकार बैतूल विधायक के प्रयास रंग लाए। बैतूल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो होगी, लेकिन बैतूल जिला अस्पताल पीपीपी मोड पर नहीं जाएगा उसका स्वरूप यथावत रहेगा। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता और डिप्टी सीएम स्वास्थ्य- चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ.राजेन्द्र शुक्ल, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, सीएस अनुराज जैन की



मौजूदगी में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में बैतूल सहित प्रदेश के 12 सरकारी जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर मेडीकल कॉलेज बनाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर न सौंपकर केवल टीचिंग और ग्रैजुएटस के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त निर्णय के लिए बैतूल विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव एवं उपमुख्यमंत्री ,स्वास्थ्य - चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ.राजेन्द्र शुक्ल को धन्यवाद ज्ञापित कर आभार माना। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बैतूल सहित म.प्र. के 12 सरकारी जिला अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा करने के बाद जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य



विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी थी। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए बैतूल सहित अन्य जिलों में भूमि भी आवंटित कर दी गई थी। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापना के प्रोजेक्ट में जिला अस्पताल को पीपीपी मोड पर देने का प्रावधान था। मेडिकल कॉलेज की स्थापना के दौरान बैतूल जिला अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त रखने के लिए

जिलेवासियों द्वारा बैतूल विधायक श्री खण्डेलवाल से लगातार मांग की जा रही थी। जिसे गंभीरता से लेकर बैतूल विधायक ने मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से पत्राचार एवं व्यक्तिगत भेंट कर जिला अस्पताल के स्वरूप को यथावत रखने के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी से अवगत कराकर पीपीपी मोड से मुक्त रखने की मांग ही। परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता एवं उपमुख्यमंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री, बैतूल विधायक तथा मुख्य सचिव की मौजूदगी में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि मेडीकल कॉलेज की स्थापना के दौरान जिला अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त रखा जाएगा। इस निर्णय के लिए बैतूल विधायक ने जिलेवासियों की ओर से मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव एवं उपमुख्यमंत्री- स्वास्थ्यमंत्री डॉ.राजेन्द्र शुक्ल का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

